







# विचार

## **सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट दिशा- निर्देश जारी करने चाहिए**

सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े एक मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देशों पर सवाल उठाकर अच्छा काम किया है। यह मामला अभिनेता कमल हासन के उस बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है। इस बयान के कारण कर्नाटक में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और कुछ नेताओं ने कमल हासन की नवीनतम फिल्म 'ठग लाइफ' दिखाने वाले सिनेमाघरों को जलाने की धमकी दी।

उच्च न्यायालय में हासन की याचिका को न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने खारिज कर दिया और अभिनेता से उनकी टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा तथा कहा कि 'किसी भी नागरिक को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है।' अदालत ने कहा कि हासन स्पष्टीकरण जारी कर सकते थे, कह सकते थे कि 'मैंने इतिहास को देखे बिना बयान दिया है' और कहा कि 'एक माफी से सब कुछ हल हो जाता... लेकिन रवैया तो देखिए।'

जस्टिस नागप्रसन्ना ने भी हासन के दावे पर सवाल उठाया, 'ये परिस्थितियां कमल हासन द्वारा पैदा की गई थीं, और उन्होंने कहा है कि वे माफी नहीं मांगेंगे। आपने कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है... किस आधार पर? क्या आप इतिहासकार हैं? या भाषाविद हैं?' अदालत ने अभिनेता द्वारा अशांति पैदा करने के बावजूद पुलिस से सुरक्षा मांगने के निर्णय पर भी सवाल उठाया। 'अब आप यहां व्यावसायिक हित के लिए आए हैं, कि पुलिस को आपके द्वारा पैदा की गई स्थिति से सुरक्षा करनी चाहिए।' कमल हासन द्वारा माफी मांगने से इंकार करने के बाद, फिल्म कर्नाटक में रिलीज नहीं की गई, जिसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका ( पी.आई.एल. ) दायर की गई।

न्यायमूर्ति उज्जल भुड़ायां और न्यायमूर्ति मनमोहन की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि कानून के शासन को भीड़ की धमकियों का बंधक नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि 'गुंडों के समूहों' को यह तय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि सिनेमाघरों में क्या दिखाया जाएगा। पीठ ने टिप्पणी की, 'यदि किसी ने कोई बयान दिया है, तो आप उसका जवाब दूसरे बयान से दे सकते हैं। आप थिएटरों को जलाने की धमकी नहीं दे सकते।' सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म के निर्माता द्वारा दायर याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय से अपने पास स्थानांतरित कर लिया और राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। इसने उच्च न्यायालय की भ्रमिका पर सवाल उठाया, विशेषकर इस सुझाव पर, कि मुद्दे को सुलझाने के लिए अभिनेता को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि किसी से उसकी टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहना न्यायालय का काम नहीं है। इसने इस बात पर जोर दिया कि एक बार जब किसी फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) से मंजूरी मिल जाती है, तो उसे रिलीज होने की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा, 'लोग इसे न देखने का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन हम धमकी और भय के आधार पर यह तय नहीं कर सकते कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं।' अदालत ने इस तर्क के समर्थन में, कि लोकतंत्र में भिन्न विचारों को अनुमति होनी चाहिए, 'मि. नाथूराम बोलतोय' नाटक मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले और इमरान प्रतापगढ़ी फैसले सहित पिछले निर्णयों का हवाला दिया।

**दुनिया में कोई फी में नहीं खिलाता, हाइट हाउस में ट्रैप  
की रोटी खाते ही मुनीर को यह बात समझ आ गयी**

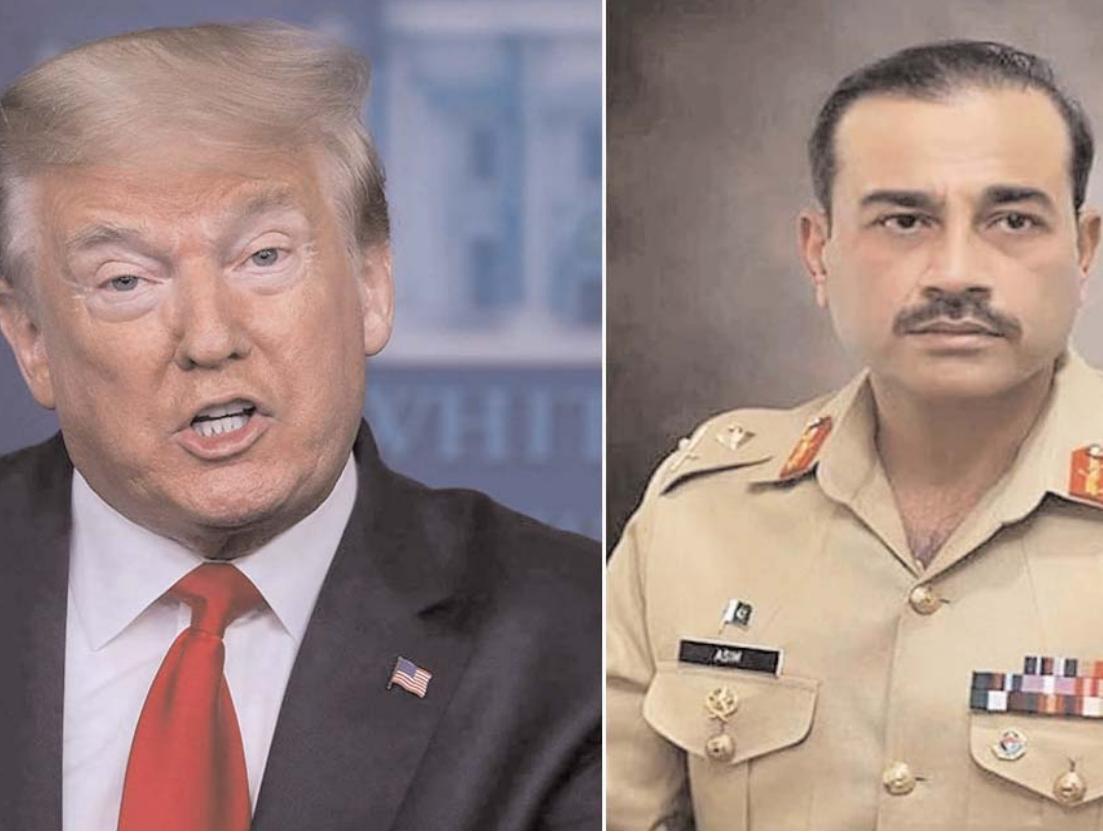
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष फ़ील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ दोपहर का भोज करके पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान में सरकार नहीं बल्कि सेना ही असली ताकत रखती है। ट्रंप ने जिस तरह से असीम मुनीर को खाना खिलाते समय कहा कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है उससे यह भी संकेत मिले कि अमेरिकी राष्ट्रपति के मन में कुछ बड़ा चल रहा है। हम आपको बता दें कि ईरान पर हमला करने की तैयारी कर चुका अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उसकी मदद करे। हम आपको याद दिला दें कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन को उखाड़ने के लिए भी अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना बेस बनाया था।

हालांकि अयूब खान, जिया-उल-हक और परवेज मुशर्रफ जैसे पाकिस्तानी सैन्य नेताओं ने अतीत में अमेरिकी राष्ट्रपतियों से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने यह मुलाकात तब की थी जब वे सैन्य तखापलट के बाद पाकिस्तान के नेता बन गए थे। हम आपको यह भी बता दें कि जिया-उल-हक और मुशर्रफ ने भी अमेरिका से अरबों डॉलर की सैन्य सहायता और अनुदान प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान को एक किराए की सेना में बदल दिया था।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में भी कहा गया है कि ट्रंप की इस पहल को मुनीर को पाकिस्तान का वास्तविक नेता मानने के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका ईरान में अपने संभावित हमलों के लिए मुनीर का समर्थन प्राप्त करना चाहता है। इसके साथ ही अमेरिका और इज़राइल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरान इस्लामी दुनिया में अलग-थलग रहे और उसे पाकिस्तान का समर्थन नहीं मिले। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप की अजीबो-गरीब नीतियों को देखते हुए, यह भी संभव है कि मुनीर को चेतावनी दी गई हो कि अगर इस्लामाबाद ने ईरान का समर्थन किया तो परिणाम भुगतने होंगे। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की है और उन्हें ईरान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन और अनुचित तथा अवैध आक्रामकता बताया है।

वाले इमरान खान की पीटीआई पार्टी के समर्थकों का आरोप है कि वह इज़राइल समर्थक हैं और अमेरिका-इज़राइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान एकमात्र इस्लामी परमाणु शक्ति बना रहे। हम आपको बता दें कि पीटीआई कार्यकर्ताओं ने ही सबसे पहले मुनीर की अमेरिका में गुस यात्रा का खुलासा किया था और आरोप लगाया था कि उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में एक इज़राइल समर्थक लॉबी समूह की बैठक में भाग लिया। उन्होंने उनके अमेरिकी सहयोगी साजिद तारार को इज़राइल का कट्टर समर्थक और फिलिस्तीनी व ईरानी मुसलमानों का दुश्मन बताया था।

जहां तक ट्रॅप और मुनीर के लंच के बाद आये अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। साथ ही उन्होंने यह दावा किया है कि मुनीर ने भारत के साथ एक विनाशकारी युद्ध को टाल दिया। ट्रॅप ने कहा, मुनीर इस युद्ध को पाकिस्तान की ओर से रोकने में बेहद प्रभावशाली था। यह भी कहा जा रहा है कि मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से लंच का निमंत्रण उस समय आया जब उन्होंने ट्रॅप को भारत-पाक परमाणु युद्ध को रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने की सिफारिश की। यह भी बताया जा रहा है कि यह लंच मीटिंग पाकिस्तानी-अमेरिकी व्यवसायी साजिद तारार के प्रयासों से आयोजित हुई, जो ट्रॅप के लंबे समय से समर्थक और अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रॅप समूह के संस्थापक हैं। तारार पिछले तीन रिपब्लिकन राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्ता रहे हैं और उनकी स्तर विचारधारा से करीबी के कारण उनके बेटे को ट्रॅप के पहले कार्यकाल में स्टेट डिपार्टमेंट में नियुक्त मिली थी। रिपोर्टों के मुताबिक तारार ने फोर सीजन्स होटल में मुनीर के लिए एक सामुदायिक स्वागत समारोह भी आयोजित किया, जिसमें सेना प्रमुख ने प्रवासी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के सच्चे राजदूत बताया और उनके रेमिंटेंस, निवेश और उपलब्धियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था और वैश्विक छवि में योगदान की सराहना की। बहरहाल, पाकिस्तान को अपने पहले कार्यकाल में धोखेबाज़ और आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह कहने वाले ट्रॅप का आतंकी देश के प्रति अचानक यू-टर्न पूरी दुनिया को चौंका रहा है। लेकिन सब यह भी समझ रहे हैं कि अमेरिका इस समय पाकिस्तान का उपयोग करना चाह रहा है। अमेरिका में तो ट्रॅप के इन पैतरों का विश्लेषण भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक डेरेक ग्रॉसमैन ने कहा, यह काफी हैरानी वाली बात है कि ट्रॅप ने मोदी को चुपचाप व्हाइट हाउस आमंत्रित करने की कोशिश की जब असीम मुनीर भी वहां लंच के लिए मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ट्रॅप को भारत-पाकिस्तान तनावों की पृष्ठभूमि और इतिहास की कोई समझ नहीं है, वह बस एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं ताकि बात में नोबेल प्रस्कार मिल सके।



चूंकि ईरान की सीमाएँ भी पाकिस्तान के साथ लगती हैं इसलिए अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान एक बार फिर उसे अपना बेस वहां बनाने दे ताकि उसके लड़ाकू विमान वहाँ से उड़ान भर सके। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान में इस बात की इजाजत वहां की सरकार नहीं बल्कि सेना ही दे सकती है इसलिए मुनीर को लंच पर बुलाया गया।

इसके अलावा इजराइल भी चाहता है कि ईरान को किसी भी मुस्लिम देश की मदद नहीं मिले, इसके लिए उसने अमेरिका से पाकिस्तान को समझाने के लिए कहा था। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं और हाल ही में पाकिस्तान ने ईरान

आग्रह ठुकरा दिया था। मोदी समझ गये थे कि यदि ट्रॉप ने अचानक उनकी और मुनीर की भेंट करवा कर दुनिया के सामने फिर से यह दावा कर दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह करवा दी है तो उनके लिए घरेलू गज़नीविक में से एक नई मस्तिष्कल जन्मी हो जायेगी।

राजनीतिक मार्च पर नई मुश्कल खड़ा हो जायगा।  
जहां तक ट्रंप और मुनीर के लंच की बात है तो बताया जा रहा है कि पहला निवाला मुंह में डालते ही मुनीर के होश उड़ गये क्योंकि वह कट्टरपंथी स्वभाव के हैं इसलिए उन्हें यह बात रास नहीं आई कि वह ईरान का साथ देने की बजाय इजराइल को अपना मिशन पूरा करते हुए देखें। मुनीर को ट्रंप की रोटी खाते ही यह बात समझ आ गयी कि दुनिया में कोई भी फी में कुछ नहीं खिलाता। वैसे भी ट्रंप राजनीतिज्ञ कम, व्यापारी ज्यादा हैं और उन्हें पता है कि पाकिस्तान के किसी भी सेनाध्यक्ष को मुंहमांगी कीमत देकर आसानी से खरीदा जा सकता है। यही काम ट्रंप ने किया और मुनीर को अपने पाले में कर लिया। वैसे, अमेरिकी राजनीति के इतिहास में यह दुर्लभ ही नहीं बल्कि अभूतपूर्व घटना है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विदेशी सैन्य प्रमुख को लंच पर बुलाए

# एफएटीएफ के निशाने पर है पाक का आतंकवाद



सीमित कर देगा दारअसल, पाकिस्तान गढ़े हुए तर्कों के आधार पर इस निगरानी संगठन एफएटीएफ को मनाने में आशिक रूप से सफल रहा था कि वह धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने के लिये अपने सिस्टम में सुधार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रबल विरोध के बावजूद इस्लामाबाद ने अंतर्राष्ट्रीय मद्रा कोष यानी आईएमएफ से एक अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। हालांकि, इस बेलआउट पैकेज के साथ कई कड़ी शर्तों का समना भी पाक को करना पड़ेगा। यूं भी यह अन्तर्राष्ट्रीय धन का गलत एवं अतिशयोक्तिपूर्ण इस्तेमाल देरसबेर विश्व के सामने आयेगा। भारत दुनिया के देशों को यह बताने और समझाने में कामयाब रहा है कि पाक न केवल आतंकवाद का समर्थन करता है, बल्कि वह आतंकवाद का पोषक भी है और वह आतंकवाद के लिए फंडिंग भी करता है। इस तरह इसे भारत की कूटनीतिक विजय कहा जा

सकता है। क्योंकि एफएटीएफ का इतना बोल्ड बयान पाकिस्तान के मुँह पर तमाचा है। एफएटीएफ की ओर से जारी अधिकारिक बयान की गहराई को समझने की जरूरत है, कि आतंकवादी हमले दुनिया भर में लोगों की जान लेते हैं, उन्हें अंग बनाते हैं और भय पैदा करते हैं। यानि एफएटीएफ ने यह मान लिया है कि पहलगाम हमला आतंकवादी वित्त पोषण के कारण ही अमल में आया। एफएटीएफ का यह बयान भारत के लिए बहुत अहम है। ध्यान रहे कि एफएटीएफ, जी-7 देशों की ओर से स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है, जो देशों की वित्तीय नीतियों का मूल्यांकन करती है। गौरतलब है कि वर्तमान में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में 24 देशों का नाम है, जो धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और

यहां यह उल्लेखनीय एवं ध्यान देने वाली बात है कि पाक को कई बार एफएटीएफ की ग्रेलिस्ट में डाला जा चुका है। इसे

पहली बार 2008 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन बाद में 2010 में इसे हटा लिया गया। इसके बाद, 2012 में पाक को फिर से इस लिस्ट में डाला गया और 2015 में इसे दुबारा हटा दिया गया। इसके बाद, पाक को जून 2018 में फिर से ग्रे लिस्ट में डाला गया था और अक्टूबर 2022 में इसे हटा लिया गया। लेकिन यह कुत्ते की ऐसी दूम हैं जिसे किनते की कड़े प्रावधानों में रखा जाये, यह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उल्लेखनीय है कि एफएटीएफ ने वैश्विक नेटवर्क में 200 से अधिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में योगदान देने वाले विशेषज्ञों का समर्थन करने के लिए आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम पर मार्गदर्शन विकसित किया है। अहम बात यह है कि एफएटीएफ के सख्त एवं कठोर व्यवहार के बाद अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के यह समझ में आने लगा है कि पाकिस्तान एक असुरक्षित एवं आतंकवादी पोषक गंतव्य बनता जा रहा है। ऐसे में एफएटीएफ के दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों की संभावना के कारण पाक की पहले से ही डांवांडोल अर्थव्यवस्था को और झटका लग सकता है।

जी-7 शिखर बैठक 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानास्किस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मेजबानी में हो रही है। इसमें जी-7 देशों के प्रमुखों के अलावा, भारत के प्रधानमंत्री नंदें मोदी, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज जैसे नेताओं को भी आमत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक के दौरान जी-7 के सदस्य देशों के राष्ट्रधर्षकों को पाक का सच और ऑपरेशन सिंधूर की सफलता के बारे में बताते हुए आतंकवाद के विरोध में संगठित होने के लिये वातावरण बना रहे हैं। भारत ने एफएटीएफ के बयान का स्वागत करते हुए कहा भी है कि यह वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख की पुष्टि करता है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी एफएटीएफ की चेतावनी को गंभीर बताते हुए कहा कि यह पाक के लिए एक और बड़ा झटका है, जिससे उसकी वैश्विक छवि और कमज़ोर हो सकती है। गौरतलब है कि भारतीय अधिकारियों ने पिछले महीने पेरिस और वॉशिंगटन में एफएटीएफ प्रतिनिधियों से बैठक कर पाक के खिलाफ नई कार्रवाई की मांग की थी।







